

वर्ष 2030 तक मलेरिया से मुक्ति का लक्ष्य

- नवनीत कुमार गुप्ता

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (इंडिया साइंस वायर) : श्रीलंका और मालदीव जैसे देश मलेरिया से पहले ही उबर चुके हैं और अब भूटान भी वर्ष 2018 तक मलेरिया के खात्मे की घोषणा कर चुका है, पर भारत में मलेरिया उन्मूलन आज भी टिकाऊ विकास का लक्ष्य हासिल करने की राह में एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है। दक्षिण एशिया में मलेरिया के 70 फीसदी मामले भारत में सामने आते हैं और इससे होने वाली 69 फीसदी मौतें हमारे देश में होती हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 1955 में जब मलेरिया पर जल्दी ही मनुष्य के विजयी होने की घोषणा की, तो लगा कि अब इस बीमारी के दिन लड़ जाएंगे, पर मलेरिया ने फिर से पलटकर वार कर दिया। आज दुनिया भर में हर साल करीब 22-50 करोड़ लोग इसके शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण लगभग 7-8 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्ष 2010 से 2015 के बीच दुनिया भर में मलेरिया के मामलों में 21 प्रतिशत कमी आई है, पर अभी भी दुनिया की करीब आधी आबादी पर मलेरिया का खतरा मंडरा रहा है। इस बार मलेरिया दिवस के मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की रोकथाम को केंद्र में रखा है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मलेरिया से मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार के जरिये गरीबी से मुक्ति एवं खुशहाल जीवन के लिए एक रणनीति तैयार की है और वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया से मुक्त करने के लक्ष्य के तहत राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना (एनएफएमई) 2016-2030 शुरुआत की गई है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए विकास से जुड़े साझेदारों और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर प्रभावी तौर पर काम करने की योजना बनाई गई है।

सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2024 तक मलेरिया की घटनाओं में इतनी कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है कि हर साल प्रति 1,000 की आबादी पर मलेरिया का एक से भी कम मामला सामने आए। राज्य सरकारों को भी नीतिगत मामलों में मलेरिया उन्मूलन को शामिल करने के लिए उत्प्रेरित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित मलेरिया की तकनीकी रणनीति (2016-2030) का हिस्सा है, जिसके तहत वर्ष 2020 तक भारत में मलेरिया के मामलों में 15 से 20 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

पिछले लगभग 300 वर्षों से मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली कुनैन आज बेअसर साबित हो रही है और क्लोरोक्विन से भी इसका कारगर इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन दवाओं के प्रति मच्छरों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है। डीडीटी और दूसरे कीटनाशकों के छिड़काव से आस जगी थी, पर इन कीटनाशकों के प्रति भी मच्छरों ने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है और अब वे ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, बल्कि शहरी इलाकों में भी पूरी ताकत से हमला बोल रहे हैं। हमारे देश की कुल आबादी में से लगभग तीन चौथाई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते हैं, जहां मलेरिया का खतरा सबसे अधिक है।

आजादी से पहले तक देश की लगभग एक चौथाई आबादी मलेरिया से प्रभावित होती थी। वर्ष 1947 में तो भारत की 33 करोड़ आबादी में से 7.5 करोड़ लोग मलेरिया का शिकार बन गए और आठ लाख लोग मारे गए। इस बीमारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1953 में 'राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम' शुरू किया, जो काफी सफल रहा और इससे मलेरिया के रोगियों की संख्या में कमी आई। उत्साहित होकर सरकार ने वर्ष 1958 में 'राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम' शुरू किया। लेकिन, डीडीटी जैसी कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव में ढील दिए जाने के कारण 1960 और 1970 के दशक में मलेरिया के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई। वर्ष 1976 में तो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत देश भर में 60.45 लाख केस दर्ज किए गए। मलेरिया की रोकथाम

के तमाम प्रयासों के कारण रोगियों की संख्या काफी घट गई, लेकिन वर्ष 1990 के दशक में यह रोग नई ताकत के साथ वापस लौट आया। कीटनाशकों के प्रति मच्छरों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने, खुले स्थानों में मच्छरों की बढ़ती आबादी, जल परियोजनाएं, शहरीकरण, औद्योगीकरण और मलेरिया परजीवी के रूप बदलते रहने के कारण भी इस बीमारी की रोकथाम करना कठिन हो गया। क्लोरोक्विन तथा मलेरिया की अन्य दवाइयों के प्रति प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम परजीवी की प्रतिरोधक क्षमता भी चिकित्सा विज्ञान से जुड़े वैज्ञानिकों के लिए सिरदर्द बनी हुई थी।

एक सूक्ष्म परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण यह रोग होता है। इस परजीवी की चार प्रजातियों प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, और प्लाज्मोडियम मलेरी से मनुष्यों को मलेरिया होता है। इसकी पांचवीं प्रजाति प्लाज्मोडियम नोलेसी जूनोटिक है। इस परजीवी को एनोफेलीज प्रजाति के मादा मच्छर फैलाते हैं। मलेरिया की पुरानी प्रचलित दवा कुनैन थी। इसे सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाया जाता था। वर्ष 1943 में क्लोरोक्विन दवा की खोज हुई, जिससे मलेरिया के उपचार में काफी मदद मिली, पर मलेरिया से बचाने के लिए टीके की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। आनुवंशिकीविद् मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के जीन्स में बदलाव करके ऐसे मच्छर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके शरीर में परजीवी जाना ही न चाहें या ऐसे मच्छर, जो मनुष्य का खून न चूसना चाहें।

हमारे देश में मलेरिया के उपचार के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। लखनऊ स्थित केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने कुछ समय पूर्व मलेरिया के इलाज के लिए 'ई-माल' तथा 'आब्लाक्विन' नामक औषधियां बनाई हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान भी मलेरिया की बेहतर दवाओं के विकास में जुटा हुआ है।

मलेरिया की रोकथाम के लिए वैज्ञानिकों का ध्यान पुराने प्रचलित और प्राकृतिक तरीकों की ओर भी गया है। मच्छरदानियों को रसायनों में भिगोने के बाद उसे सुखाकर काम में लाया जा रहा है। ऐसी दवा-बुझी मच्छरदानियों से कई विकासशील देशों में लोग मलेरिया की मार से बच रहे हैं। मच्छरों का लार्वा खाने वाली मछलियों की संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया जा रहा है। इसके अलावा मेंढक और अन्य पानी में रहने वाले जीवों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस प्रकार पूरी दुनिया में मलेरिया से निपटने के विभिन्न उपायों को खोजा जा रहा है, ताकि इस बीमारी से निजात पाया जा सके।

मलेरिया के प्रति जागरूकता के प्रयासों के तहत वर्ष 2007 से प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया के प्रति समझ और इसकी रोकथाम के प्रयासों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना ही मलेरिया दिवस मनाए जाने का प्रमुख मकसद है।

(इंडिया साइंस बायर)